International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 2, Issue 7, pp 295-300, July 2025

समावेशी शिक्षा में मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के समाधान: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन भारत के संदर्भ में

Mrs. Kiran Tiwari

Assistant Professor
Department of Education
B.T. Institute of Excellence, Makronia, Sagar, 470004
Email: ***kirantiwari15041982@gmail.com***

सारांश

समावेशी शिक्षा वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवशकता बन चुकी है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी विद्यार्थियों (विशिष्ट बालक एवं समान्म बालक) को समान एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना है अर्थात समावेशी शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें विभिन्न सामाजिक, मानसिक या शारीरिक स्थितियों वाले बालक एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्राप्त करते हैं l इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी बच्चों को समान अवसर एवं सहभागिता सुनिश्चित करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बने 'ओर एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकें। इस दिशा में काम करते समय कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएँ आती है जैसे- आत्मगौरव में कमी, अलगाव की भावना, सामाजिक भेदभाव, आपसी सहयोग की कमी, अभिभावकों की आशंकाएं, शिक्षकों की मानसिक थकान एवं शिक्षण सामग्री की कमी आदि ये समस्याएं छात्रों के मानसिक स्वास्थ पर गहरा प्रभाव डालती हैं। यह शोध विशेषकर भारत में समावेशी शिक्षा के तहत अध्ययनरत छात्रों एवं संबंधित शिक्षको के बीच इन चुनौतियों का विश्लेषण करेगा l इस शोध का मुख्य उदेश्य समावेशी शिक्षा में मनोवैज्ञानिक समस्याओं की पहचान करना तथा उनके समाधान प्रस्तुत करना है। यह अध्ययन नीति निर्माताओं, स्कूलों एवं मनोवैज्ञानिकों को एक बेहतर शिक्षा प्रणाली विकसित करने में मदद करेगा जिसमें समावेशिता के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए।

संकेत शब्द: समावेशी शिक्षा, समान अवसर, आत्मनिर्भर, मानसिक-स्वास्थ, शिक्षा प्रणाली आदि।

प्रस्तावना

आज के शैक्षिक परिवेश में समावेशी शिक्षा एक ऐसीअवधारणा बनकर उभरी है, जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों- चाहे वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्याएं से जूझ रहे हो- को समान और गुणबत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत मुख्य रूप से उसे समय से मानी जाती है, जब भारत सरकार द्वारा विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा व्यवस्था (IEDC) की शुरुवात् 1974 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य विकलांग छात्रों और सामान्य छात्रों को एक साथ एकीकृत कराया गया। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शारीरिक एवं मानसिक विकलांग छात्रों को सामान्म छात्रों के साथ सामान्य कक्षा में रखने की बात की गई हैं। आगे चलकर यह समावेशन केवल विकलांग छात्रों तक सीमित न

होकर सभी प्रकार की विविधता और विषमता जैसे- लैंगिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद, धार्मिक विभेद, भाषाई विभेद, सामाजिक विभेद,सांस्कृतिक विभेद या किसी भी प्रकार की विभिन्नताओ को समावेशी शिक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। [1 & 4] अर्थात समावेशी शिक्षा सभी छात्रों की विशिष्टताओं और क्षमताओं पर ध्यान न देकर उनको विकसित होने का समान अवसर प्रदान करती हैं।

- **उद्देश्य:** समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, सहभागिता और न्यायपूर्ण अवसर प्रदान करना है ताकि हर विधार्थी जिसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो उसे शिक्षा का समान अवसर मिले।[11]

Table 1: समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य

1.	सभी के लिए समान शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना ।	प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमताओं की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना।
2.	भेदभाव रहित वातावरण तैयार करना।	जाति, लिंग, धर्म, वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ऐसा शैक्षणिक वातावरण बनाना
3.	बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना	विशेष आवश्यकता वाले बच्चो को सामान्य विधालयों में शिक्षा प्राप्त कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना
4.	नीति निर्माण मे समान अवसर सुनिश्चित करना ।	सभी बच्चों को ध्यान में रखकर शैक्षिक नीतियों की योजनाएं बनाई जाए।
5.	बाधाओ को पहचानकर उन्हें दूर करना।	विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक बाधाओं की पहचान करके उन्हें संसाधनों और नीतियों के द्वारा दूर करना ।
6.	नई तकनीकी सहायता प्रदान करना ।	शिक्षा की नई तकनीकीयों द्वारा (सहायक उपकरण, ICT, लेग्वेज आदि) बच्चों की शिक्षा को सरल बनाना ।
7.	शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के प्रति प्रेरित करना ।	शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक व सक्षम बनाना ।

8.	सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना।	शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामाजिक एकता व सहयोग की भावना का विकास करना

भारत में समावेशी शिक्षा का प्रारंभ :

भारत में समावेशी शिक्षा का प्रारंभ 1974 में इंटरग्रेटेड एजुकेशन फार डिसेबल्ड चिल्ड्रन (IEDC) कार्यक्रम के तहत शुरू हुआ, जिसमें सामान स्कूलों में विकलांग बच्चों को शिक्षा देने की पहल हुई l इसके बाद लगातार हमारे देश में समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम, अभियान, योजनाएं और अधिकारों को मान्यता दी गई जैस:

1. 1986- राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2. 1995- विकलांगजन अधिनियम (PWD ACT)
3. 2005- सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
4. 2009- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)
5. 2016- दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम ACT
6. 2020- नई शिक्षा नीति (NEP 2020)[1, 8, 9 &10]

- **भारत की वर्तमान स्थिति:**

वर्तमान समय में भारत में NEP 2020 के तहत सभी छात्रओ को उनकी जरूरतों को ध्यान में। रखते हुए सरकारी स्कूलों में रैंप, बेल सामग्री, विशेष शिक्षक आदि की व्यवस्था बढ़ाई गई है तथा शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण (Inclusive B.Ed.,CRC,RCI कोर्स)दिया जा रहा है।[3]

इसके अलावा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म (pathshala, Diksha) पर समावेशी सामग्री को जोड़ा गया है l किंतु इसके बावजूद भी समावेशी शिक्षा में कोई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक चुनौतियां सामने आ रही है जो किसी न किसी रूप में समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं l[6]

- **समावेशी शिक्षा में मनोवैज्ञानिक चुनौतियां:**

भारत में समावेशी शिक्षा में आने वाली प्रमुख मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है:[2][5]

1. आत्म सम्मान की कमी: विशेष आवश्यकता वाले छात्र समान्य छात्रों की अपेक्षा स्वयं को कमतर मानने लगते है जिससे उनका आत्मविश्वास घटता है।
2. सामाजिक अलगाव: विशेष बच्चे सामान्य बच्चों के साथ आसानी से घुल- मिल नहीं पाते, जिससे वे अकेलापन महसूस करते हैं।

3. आत्म स्वीकृति की कमी: कई बार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपनी विशेषता स्वीकार करने में आत्मग्लानि होती है।
4. सहयोगी माहोल की कमी: कई बार स्कूलो में भी सहयोगी तथा सुरक्षित वातावरण का अभाव छात्रों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है।
5. व्यवहार संबंधी समस्याएँ: कुछ बच्चों में विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं के कारण भी असामान्य व्यवहार दिखाई देता है।
6. सहपाठियों की असंवेदन शीलता: कई बार सामान्य छात्र भी विशेष बालकों को अपने से अलग रखते है तथा उनका मजाक उडाते हैं।
7. शिक्षकों का मानसिक तनाव: समावेशी कक्षाओं में कई बार शिक्षकों को विशेष छात्रों को पढ़ाना चुनौतीपूर्ण होता है जिसमे शिक्षकों मे भी मानसिक तनाव व थकान की समस्याएं होती है।
8. अभिभावकों की चिंता: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता सामाजिक दबाब, बच्चों के भविष्य की चिंता तथा शिक्षा की अनिश्चिता को लेकर मानसिक तनाव में रहते हैं
9. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी: अधिकांश विद्यालयों में काउंसलर,स्पेशल एजुकेटर या मनोवैज्ञानिक सुविधा उपलब्ध नहीं होती है।
10. मूल्यांकन का मानसिक दबाव : सामान्य मापदंडो पर परीक्षा देने का दबाव विशेष छात्रों पर अधिक मानसिक तनाब डालता है।
11. अभिव्यक्ति की झिझक: विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अपनी समस्याएं या भावनाएँ व्यक्त करने में झिझक होती हैं।
12. असकलता का डर: परीक्षा में असफलता के डर से कई बार विशेष छात्र कुछ सीखने से बचते है तथा प्रयास भी नहीं करते हैं।
13. आत्म प्रभावकारिता में कमी: कुछ शिक्षकों के पास छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल तथा ज्ञान का अभाव होता है जिससे आत्म प्रभावकारिता में कमी होती हैं।
14. सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में उचित तालमेल न होना: सामान्य शिक्षक तथा विशिष्ट शिक्षकों में आपसी तालमेल ना होने के कारण भी विशेष छात्रों को कई मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है l
15. विद्यालय,छात्र, शिक्षक व अभिभावक के बीच उचित समन्वय ना होना: कई बार विद्यालय ,छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के बीच उचित तालमेल न हो पाने के कारण भी कई मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है l

समाधान

समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से तभी प्राप्त किया जा सकता हैं, जब विद्यालय, शिक्षक छात्र,अभिभावक और समुदाय का पूर्ण सम्वय हो, जैसे- [12]

1. **शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता**
   - ❖ समावेशी शिक्षा पर विशेष प्रशिक्षण देना जिससे वे विविध मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जरूरतों को समझ सकें।

- ❖ मनोवैज्ञानिक मुद्दों की पहचान और प्रबंधन की स्किल्स विकसित करना।

2. **परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता**
   - ❖ विद्यालयों में काउंसलर की नियुक्ति जो छात्रों की मानसिक समस्याओं को पहचान सकें।
   - ❖ बच्चों और अभिभावकों दोनों को मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा देना।
3. **सहयोगात्मक शिक्षण (को-टीचिंग)**
   - ❖ विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षक मिलकर पढ़ाएं ताकि हर विद्यार्थी को ज़रूरत के अनुसार मदद मिले।
4. **शिक्षण सामग्री का विविधीकरण**
   - ❖ छात्रों की जरूरतों के अनुसार वैकल्पिक शिक्षण सामग्री और तकनीक का प्रयोग करना।
   - ❖ ब्रेल, साइन लैंग्वेज, ऑडियोबुक, चित्र आधारित शिक्षण आदि का उपयोग।
5. **सहपाठियों में संवेदनशीलता विकसित करना**
   - ❖ सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम चलाना ताकि सामान्य छात्र भी समावेशी भावना को समझें।
   - ❖ सहपाठी का सहयोग मानसिक समर्थन देता है।
6. **अभिभावकों की भागीदारी**
   - ❖ पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे वे बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को समझ सकें।
   - ❖ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को घर पर भी सहयोग मिल सके ।
7. **मूल्यांकन पद्धतियों में लचीलापन**
   - ❖ एक जैसे मूल्यांकन के बजाय व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार लचीला मूल्यांकन करना।
   - ❖ समय, भाषा, और माध्यम में छूट देना।
8. **समावेशी नीति निर्माण और क्रियान्वयन**
   - ❖ सरकार और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा स्पष्ट समावेशी नीतियाँ बनाना और उन्हें लागू करना।
   - ❖ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में शिक्षा क्षेत्र को जोड़ना।

निष्कर्ष:

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे को समान अवसर और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है, चाहे वह किसी भी मानसिक, शारीरिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से क्यों न हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ एक बड़ी बाधा बनती हैं, जैसे - आत्मविश्वास की कमी, अस्वीकृति की भावना, संप्रेषण कठिनाइयाँ और सामाजिक दूरी आदि, इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शिक्षकों का संवेदनशील और प्रशिक्षित होना, स्कूलों में परामर्श सेवाओं की व्यवस्था, लचीली मूल्यांकन प्रणाली, सहपाठियों में सहानुभूति का विकास तथा अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जब इन समाधानों को समन्वित रूप से लागू किया जाता है, तो समावेशी शिक्षा न केवल सैद्धांतिक बल्कि व्यावहारिक रूप से सफल होती है। अतः, समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक प्रशिक्षण, सहयोग, और नीति निर्माण सभी को समाहित किया जाए, अनिवार्य है।

संदर्भ सूची :

1. https://afeias.com/wp-content/uploads/2016/01/yojana-hindi1.pdf
2. UNICEF (2021): Education for every ability, toward inclusive education in India
3. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

4. यूनेस्को (2009). Inclusive Education report in India, समावेशी शिक्षा: भविष्यका मार्ग.
5. Gupta R, 2020, Psychological barriers in inclusive education: A study of Indian context.
6. शर्मा, यू. एवं दास, ए. (2015)। भारत में समावेशी शिक्षा: अतीत, वर्तमान और भविष्य । अंतरराष्ट्रीय विशेष शिक्षा पत्रिका.
7. एनसीईआरटी। (200८ फोकस समूह की स्थिति पत्रिकाः विशेष आ भों वाले बच्चों की शिक्षा। एचटीटीपीएस://एनसीईआरटी.न.पीडीएफ/फोकस-ग्रुप/एड
8. राव, एस. (2003)। भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पत्रिका, 17(4), 507-5181
9. भारत सरकार। (2009)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (रते)।
10. विश्व स्वास्थ्य संगठन । (2021)। विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक कल्याण।
11. “समावेशी शिक्षा की चुनौतियां एवम् समाधान एक श्लेषणात्मक अध्ययन “ डॉ.सुधीर कुमार सिंह, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR).